जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

चूरू

Rashtradoot

epaper.rashtradoot.com

फोनः- 256906, 256907, फैक्सः- 01562-256908 वर्षः 17 संख्याः 317 प्रभात चूरू, मंगलवार 17 मार्च, 2026 पो. रजि. न. चूरू/084/2019-21 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रु.

बेबस से ट्रंप ने नाटो देशों से मदद मांगी, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ को खुलवाने के लिए

सभी नाटो सदस्यों ने यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि यह युद्ध यूरोपीय देशों का युद्ध नहीं है

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 16 मार्च। डॉनल्ड ट्रम्प का अहंकार कुछ समय पहले तक सातवें आसमान पर था। वे अपने ओवल ऑफिस में मीडिया के सामने कई देशों के प्रधानमंत्रियों और राष्ट्रपतियों को शर्मिंदा करने से नहीं चूकते थे।

अब, दुनिया ईरान के सामने डॉनल्ड ट्रम्प की बेइज्जती देख रही है, क्योंकि वे नाटो के सहयोगी देशों से मिन्नतें कर रहे हैं कि वे उन्हें उस जाल से बाहर निकालें, जो उन्होंने खुद ही होर्मुज़ स्ट्रेट में अपने लिए बुना था। युद्ध अब तीसरे सप्ताह में प्रवेश कर चुका है और इसके समाप्त होने की कोई संभावना दिखाई नहीं देती। यह स्थिति ट्रम्प के उस दावे के बिल्कुल विपरीत है, जिसमें उन्होंने कहा था कि यह तेज और छोटा युद्ध होगा, जो ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं को समाप्त कर देगा।

ट्रम्प की मदद की अपील के जवाब में, यूनाइटेड किंगडम ने इस विचार को सिरे से खारिज कर दिया। वहाँ के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने कहा कि उनका देश इस व्यापक युद्ध में शामिल नहीं होगा। स्टार्मर ने स्पष्ट रूप से कहा कि यह "हमारा युद्ध" नहीं है, जिसमें ब्रिटेन को खींचा जाए।

याद होगा कि ओवल ऑफिस में दुनिया के मीडिया के सामने हुई एक बैठक में डॉनल्ड ट्रम्प ने तिरस्कार भरे अंदाज़ में स्टार्मर से पूछा था कि क्या उन्हें खुद पर इतना भरोसा है कि वे

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- सभी नाटो सदस्य, उस अपमान का बदला ले रहे हैं, जो अपने ऑफिस, वाइट हाउस के "ओवल ऑफिस" में राष्ट्रपति ट्रंप ने किया था। ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुल्लम खुल्ला खूब तिरस्कृत करते हुए ट्रंप ने कटाक्ष किया था कि क्या यूरोपीय देश, रूस का सामना करने के लिए तैयार हैं, अमेरिका की सहायता के बिना।
- पर, अब अमेरिका उन्हीं यूरोपीय देशों से सहायता मांग रहा है, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ को जहाज़ों के आवागमन के लिए खुलवाने के लिए।
- अब यह भी उजागर हो गया है कि ट्रंप के इस दावे में कुछ दम नहीं है कि अमेरिकी नौसेना के संरक्षण में वो कॉमर्शियल सामान ले जा रहे जहाजों को सुरक्षित स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ पार करवा देंगे। ईरानी मिसाइल के बमबारी की क्षमता के सामने अब अमेरिकी नौ सेना स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ में प्रवेश करने का साहस नहीं जुटा पा रही।
- ट्रंप की यह गर्वोक्ति भी मिथ्या साबित हुई कि अमेरिका के आक्रमण के कारण ईरान की समस्त नौ सेना तहस-नहस हो चुकी है। लोग सवाल उठा रहे हैं, अगर ट्रंप के वक्तव्य में सच्चाई है तो अमेरिका क्यों यूरोपीय देशों से मदद मांग रहा है, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ को आवागमन के लिए खुलवाने के लिए।

संसद में सुरक्षा अलार्म बजा

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 16 मार्च। सोमवार को संसद के एक प्रवेश द्वार पर एक बूम बैरियर गिर जाने से तुरंत सुरक्षा अलार्म बजने लगा और क्विक रिएक्शन टीन (क्यूआरटी) तुरंत सक्रिय हो गई। यह घटना संभवतः तेज़ हवा के कारण हुई एक तकनीकी खराबी से हुई।

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बम के वरिष्ठ अधिकारी, जो संसद भवन परिसर की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हैं, तुरंत मौके पर पहुंचे और स्थिति का आकलन किया। सूत्रों के अनुसार जांच में पाया गया कि कोई सुरक्षा खतरा नहीं था।

कुछ समय बाद विजय चौक के पास स्थित इस गेट से वाहनों की सामान्य आवाजाही फिर से शुरू कर दी गई।

सूत्रों ने बताया कि बूम बैरियर, जिसे उठाए बिना कोई वाहन अंदर प्रवेश नहीं कर सकता हैं, अचानक नीचे आ गया। माना जा रहा है कि यह तेज़ हवा

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- हवा के कारण पैदा हुई तकनीकी खराबी से बूम बैरियर अचानक गिर गया तो सुरक्षा अलार्म बज उठा, बाद में सुरक्षा टीम तुरंत एक्टिव हो गई, पता चला अलार्म झूठा था।

बिहार में महागठबंधन "लॉयल्टी टैस्ट" में असफल हुआ

महागठबंधन के प्रत्याशी को जीतने के लिए 41 वोट चाहिए थे, पर, चार विधायक आए ही नहीं

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 16 मार्च। यदि दस राज्यों की 37 राज्यसभा सीटों के लिए हुए चुनावों को विपक्षी दलों की वफादारी की परीक्षा माना जा रहा था, तो कम से कम बिहार में ये दल इस परीक्षा में खरे नहीं उतर सके।

सोमवार को सत्तारूढ़ भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए ने बिहार की सभी पाँच राज्यसभा सीटों पर आसानी से जीत हासिल कर ली, जबकि महागठबंधन एक भी सीट नहीं जीत पाया, क्योंकि विपक्ष के चार विधायक मतदान के समय अनुपस्थित रहे।

इन चुनावों से पहले असामान्य राजनीतिक गठबंधन बनाए गए और पुरानी दुश्मनियों को भुला दिया गया था, जिसके कारण 37 में से 26 उम्मीदवार निर्विरोध चुन लिए गए। निर्विरोध चुने गए नेताओं में वरिष्ठ राजनेता और एनसीपी के संस्थापक शरद पवार, कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी, केन्द्रीय मंत्री रामदास अठावले, पीएमके प्रमुख अंबुमणि रामदास, बंगाल के भाजपा नेता राहुल सिन्हा और डीएमके के वरिष्ठ नेता त्रिची शिवा शामिल हैं।

- बिहार में कुल 5 सीटों पर राज्यसभा चुनाव होना था, सभी 5 सीटें एनडीए ने जीत ली हैं। एनडीए के विजयी प्रत्याशी हैं, नितिन नबीन, शिवेश कुमार, नीतीश कुमार, रामनाथ ठाकुर और उपेन्द्र कुशवाहा।
- पांचवी सीट के लिए राजद ने अपना प्रत्याशी खड़ा किया था। महागठबंधन के पास कुल 35 वोट थे। शेष 6 वोटों की कमी के लिए ओवैसी की पार्टी के 5 और बसपा के एक विधायक का समर्थन पक्का कर लिया गया, लेकिन मतदान के समय कांग्रेस के तीन और राजद का एक विधायक गैर हाजिर रहा, नतीजा यह रहा कि महागठबंधन हार गया।
- कांग्रेस के तीनों विधायक, सुरेन्द्र कुशवाहा, मनोज बिस्वास व मनोहर प्रसाद सिंह फोन बंद कर गायब हो गए थे, वहीं राजद के फैसल रहमान ने अपनी माँ की बीमारी को गैर हाजिरी का कारण बताया।

बिहार में महागठबंधन को बड़ी निराशा हाथ लगी। अंतिम समय में गठबंधन मजबूत करने के बावजूद, वह पाँचवीं सीट जीतने के लिए आवश्यक 41 वोटों का आंकड़ा पार नहीं कर पाया।

आरजेडी के पास 35 विधायक थे, जो जीत के लिए जरूरी संख्या से छह कम थे। इसलिए पार्टी ने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के पाँच विधायकों का समर्थन हासिल कर लिया था। एकमात्र बीएसपी विधायक ने भी महागठबंधन के उम्मीदवार को समर्थन देने का वादा किया था, जबकि उम्मीद थी कि कांग्रेस के तीन विधायक

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'आर्थिक अनुदान सीधे ईरानी दूतावास में ही जमा कराएं'

ईरानी दूतावास ने भारत के अपने शुभचिंतकों से अनुरोध किया

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 16 मार्च। इज़राइल, अमेरिका और ईरान से जुड़े बढ़ते संघर्ष का असर अब युद्धक्षेत्र से बहुत दूर तक दिखाई देने लगा है। नई दिल्ली में ईरानी दूतावास ने अपने शुभचिंतकों से अपील की है कि वे सीधे दूतावास में नकद दान करें, क्योंकि सामान्य बैंक ट्रांसफर के माध्यम से धन प्राप्त करने में उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

यह अनुरोध इस बात को उजागर करता है कि पश्चिम एशिया में चल रहा भू-राजनीतिक टकराव किस तरह वैश्विक वित्तीय प्रणाली से टकरा रहा है। राजनयिकों और विश्लेषकों का कहना है कि यह व्यवधान केवल तकनीकी कारणों से नहीं है। बल्कि यह वॉशिंगटन के नेतृत्व वाले अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों के प्रभाव को दर्शाता है, जिन्होंने लंबे समय से ईरानी संस्थाओं से जुड़े वित्तीय लेन-देन को सीमित कर रखा है।

अमेरिकी वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल (ओएफएसी) इन प्रतिबंधों को

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- एक्स पर लिखी एक पोस्ट में ईरानी दूतावास ने कहा, हम भारत के उन लोगों का धन्यवाद करते हैं, जो युद्ध ग्रस्त नागरिकों की मदद करना चाहते हैं, लेकिन तकनीकी कारणों से ऑनलाइन माध्यम से अनुदान बैंक खाते में प्राप्त करना कठिन हो गया है, इसलिए हम आग्रह करते हैं कि अनुदान सीधे दूतावास में दिया जाए।
- उन्होंने गूगल पे जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग नहीं करने का आग्रह भी किया।
- इससे स्पष्ट संकेत मिलता है कि ईरान पर अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों का दूरगामी असर हो रहा है, यहाँ तक कि वे देश जो अमरीकी प्रतिबंधों को नहीं मानते हैं, उनके वित्तीय संस्थानों से भी लेन देन नहीं हो जा रहा है।

खार्ग आईलैंड पर सेना भेजेंगे ट्रंप?

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 16 मार्च। खबरों के अनुसार, अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प कथित तौर पर खार्ग द्वीप पर कब्ज़ा करने की संभावना पर विचार कर रहे हैं। यह फारस की खाड़ी में स्थित एक

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- अमेरिकी अधिकारियों ने कहा, अगर तेहरान की नाकेबंदी के कारण टैंकर फारस की खाड़ी में फंसे रहते हैं तो ट्रंप तेहरान के प्रमुख तेल भंडार, खार्ग आईलैंड पर कब्जा करने के लिए सेना भेज सकते हैं।

खाड़ी वॉर पर भ्रामक पोस्ट करने के आरोप में 19 भारतीय गिरफ्तार

दो चरणों में गिरफ्तारियाँ की गई हैं, पहले चरण में शनिवार को 2 व सोमवार को 17 भारतीयों को गिरफ्तार किया गया

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 16 मार्च। संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने 35 लोगों, जिनमें 19 भारतीय शामिल हैं, की गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं। इन पर आरोप है कि इन्होंने सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो पोस्ट किए, जिनमें मध्य-पूर्व में चल रहे युद्ध से जुड़ी भ्रामक या मनगढ़ंत सामग्री थी। ज्ञातव्य है कि यह युद्ध पिछले महीने के अंत में तब शुरू हुआ था, जब अमेरिका-इज़रायल बलों ने ईरान पर हवाई हमले किए थे।

दुबई के अधिकारियों ने कहा कि जांच में सामने आया कि आरोपियों ने डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके क्षेत्रीय तनाव से जुड़ी फर्जी फुटेज और कथाएँ फैलायीं। उनके खिलाफ त्वरित (फास्ट-ट्रैक) मुकदमा चलाया जाएगा।

यह कार्रवाई दो चरणों में की गई। ताज़ा सूची में विभिन्न देशों के 25 लोग शामिल हैं, जिनमें 17 भारतीय हैं। इससे पहले शनिवार को 10 लोगों, जिनमें दो भारतीय थे, की गिरफ्तारी का आदेश दिया गया था।

यूएई के अटॉर्नी जनरल डॉ. हमद सैफ अल शम्स ने एक बयान में कहा कि यह कदम डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रखी गई कड़ी निगरानी के बाद उठाया गया है, ताकि झूठी जानकारी और कृत्रिम (एआई से बनाई गई) सामग्री के प्रसार को रोका जा सके, जो

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- जाँच में सामने आया कि इन्होंने डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर फर्जी फुटेज और समाचारों को प्रसारित किया, इन सभी पर फास्ट ट्रैक मुकदमा चलेगा तथा यूएई के कानून के अनुसार, एक साल की कैद व एक लाख दिरहम का जुर्माना हो सकता है।
- यूएई के अटॉर्नी जनरल हमद अल शम्स ने कहा, इन लोगों पर ईरानी हमलों के महिमा मंडन, ईरान के नेतृत्व की तारीफ करने का आरोप भी है।
- अब तक कुल 35 लोग गिरफ्तार हुए हैं, इनमें से 10 लोगों को शनिवार को गिरफ्तार किया गया, उनमें 2 भारतीय शामिल हैं।
- दूसरे चरण में एक समूह में सात आरोपी पकड़े गए, इनमें 5 भारतीय, एक नेपाली, एक बांग्लादेशी है तथा दूसरे समूह में गिरफ्तार 6 लोगों में से 5 भारतीय व एक पाकिस्तानी है।